Auditing

Audit of Limited Companies under the Companies Act, 2013

By:

Santosh Kumar Lal

Dept. of Commerce

Sariya College, Suriya

Audit of Limited Companies under Companies Act, 2013

Audit means an independent examination of financial statements of a company to express an opinion on whether they give a true and fair view.

अंकेक्षण (Audit) का अर्थ है कंपनी के वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र जांच करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सही और निष्पक्ष (True and Fair) स्थिति को दर्शाते हैं।

Types of Limited Companies

- Private Limited Company
- Public Limited Company
- One Person Company (OPC)

- प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
- पब्लिक लिमिटेड कंपनी
- एक व्यक्ति कंपनी (OPC)

Appointment of Auditor (Section 139)

- First auditor appointed by Board within 30 days of incorporation
- Subsequent auditors appointed by shareholders in AGM
- Term: 5 years (subject to ratification earlier, now not required after amendment)

- पहला ऑडिटर कंपनी के बोर्ड द्वारा 30 दिनों के भीतर नियुक्त किया जाता है
- बाद के ऑडिटर AGM में शेयरधारकों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं
- कार्यकाल: 5 वर्ष

Removal of Auditor (Section 140)

- Auditor can be removed before expiry of term by passing a special resolution
- Prior approval of Central Government required

- ऑडिटर को कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाने के लिए विशेष प्रस्ताव (Special Resolution) आवश्यक है
- केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है

Eligibility of Auditor (Section 141)

Eligible:

- Chartered Accountant in practice

Disqualified:

- Body corporate (except LLP)
- Officer/employee of company
- Person holding securities in company

योग्यता:

- प्रैक्टिस करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट

अयोग्यता:

- बॉडी कॉर्पोरेट (LLP को छोड़कर)
- कंपनी का कर्मचारी या अधिकारी
- कंपनी के शेयर रखने वाला व्यक्ति

Powers of Auditor (Section 143)

- Right to access books of accounts
- Right to seek information and explanations
- Right to attend general meetings

- खातों की पुस्तकों तक पहुंच का अधिकार
- जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार
- सामान्य बैठकों में भाग लेने का अधिकार

Duties of Auditor

- Report whether financial statements give true and fair view
- Comply with auditing standards
- Detect frauds and report them
- Ensure proper internal controls
- यह रिपोर्ट करना कि वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष हैं
- अंकेक्षण मानकों का पालन करना
- धोखाधड़ी (Fraud) का पता लगाना और रिपोर्ट करना
- आंतरिक नियंत्रणों की जांच करना

Auditor’s Report (Section 143)

The auditor must report on:

- Financial statements
- Adequacy of internal financial controls
- Observations or comments

ऑडिटर को निम्न पर रिपोर्ट देनी होती है:

- वित्तीय विवरण
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता
- टिप्पणियाँ और अवलोकन

Rotation of Auditor (Section 139(2))

- Applicable to certain classes of companies
- Individual auditor: 5 years
- Audit firm: 10 years
- कुछ कंपनियों में ऑडिटर रोटेशन अनिवार्य है
- व्यक्तिगत ऑडिटर: 5 वर्ष
- ऑडिट फर्म: 10 वर्ष

Audit Committee

- Mandatory for listed and certain public companies
- Oversees financial reporting and audit process

- सूचीबद्ध और कुछ सार्वजनिक कंपनियों में अनिवार्य
- वित्तीय रिपोर्टिंग और अंकेक्षण प्रक्रिया की निगरानी करता है

Internal Audit (Section 138)

- Mandatory for prescribed classes of companies
- Conducted by internal auditor

- कुछ कंपनियों के लिए अनिवार्य
- आंतरिक ऑडिटर द्वारा किया जाता है

Cost Audit (Section 148)

- Applicable to specified industries
- Conducted by cost accountant

- विशेष उद्योगों पर लागू
- कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है

Secretarial Audit (Section 204)

- Mandatory for listed companies and certain public companies
- Conducted by Company Secretary

- सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य
- कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है

Fraud Reporting

- Auditor must report fraud to Central Government if amount exceeds prescribed limit

- यदि धोखाधड़ी निर्धारित सीमा से अधिक हो, तो ऑडिटर को केंद्र सरकार को रिपोर्ट करना होता है

Penalties for Auditor

- Fine and imprisonment for misconduct
- Liability for fraud and negligence

- दुराचार के लिए जुर्माना और कारावास
- धोखाधड़ी और लापरवाही के लिए उत्तरदायित्व

✍️ Conclusion

Audit under the Companies Act, 2013 ensures transparency, accountability, and reliability of financial reporting in limited companies.

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अंकेक्षण कंपनियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।